



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 3, 2005/वैशाख 13, 1927

No. 61]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 2005/VAISAKHA 13, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 28 अप्रैल, 2005

सं. टीएमपी/80/2000-सीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, वर्तमान दरमान की वैधता तथा वेतन, दिहाड़ी और पेंशन बकाया की मद में देयताओं के भुगतान हेतु निर्धारित दर के विस्तार के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएमपी/80/2000-सीपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास

आवेदक

जादेश

(अप्रैल 2005 के 25वें दिन पारित)

यह प्रकरण वर्तमान दरमान की वैधता तथा वेतन, दिहाड़ी और पेंशन बकाया की मद में देयताओं के 31 मार्च, 2005 के बाद भुगतान हेतु निर्धारित दर के विस्तार के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 कार्गो और पोत संबंधी प्रभारों के विषय में कोलकाता पत्तन न्यास का दरमान पिछली बार अप्रैल 2001 में संशोधित किया गया था जो अगले दो वर्ष तक वैध था। वेतन, दिहाड़ी तथा 31 दिसम्बर, 2000 तक जारी हुए सरकारी आदेशों से उद्भूत सेवा निवृत्ति-लाभों के बकाया की मद में देयताओं के भुगतान हेतु केओपीटी को वित्तीय वर्ष 2001-02 से आरम्भ करते हुए 4 वर्ष की अवधि के लिए, दरमान में अधिसूचित विभिन्न प्रभारों की एक प्रतिशतता के रूप में एक विशेष दर लगाने की अनुमति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए विशेष दरों का निर्धारण पत्तन उपयोगकर्ताओं द्वारा देय विभिन्न प्रभारों के 10% के रूप में किया गया था। आरम्भिक दो वर्षों के अंत में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद, बाद की अवधि के लिए विशेष दर की मात्रा निर्धारित की जानी थी।

2.2. तत्पश्चात्, केओपीटी के प्रस्ताव पर, वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक लागू होने वाले प्रमारों के 10% के रूप में विशेष दर लगाने की अनुमति जारी रखी गई और तदनुसार दरमान की वैधता बढ़ाई गई। केओपीटी को निदेश दिया गया कि वह अधिकतम सितम्बर 2004 तक कोलकाता पत्तन न्यास में सम्पदा किसानों की समीक्षा के प्रस्ताव के साथ-साथ अपने दरमान की सामान्य समीक्षा का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दे।

3.1. केओपीटी ने सूचना दी है कि उसने दरमान के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है और उसने बताया कि यह प्रशुल्क प्रस्ताव, न्यासी मंडल के विचार-विमर्श के लिए उसके सामने, उसकी अगली बैठक में रखा जाएगा। यहाँ इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि उसी समय, पोत परिवहन, सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) ने हाल ही में, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 111 के अन्तर्गत, प्रशुल्क निर्धारण के लिए संशोधित मार्गदर्शी जारी किए हैं। एनएसआरटीएच से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण ने प्रशुल्क निर्धारण हेतु संशोधित मार्गदर्शियों को 31 मार्च 2005 को अधिसूचित करवाया है।

3.2. संशोधित मार्गदर्शियों में, पत्तन न्यास द्वारा प्राप्य रायल्टी / राजस्व भाग के व्यवहार, परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण, निवेशित पूंजी पर प्राप्ति की गणना, मूल्यह्रास आदि की गणना इत्यादि के संदर्भ से प्रशुल्क संशोधन निर्धारण हेतु लागत विवरणी प्रस्तुत करते समय अनुसरण करने के लिए विशिष्ट मार्गदर्शियों की व्यवस्था की गई है। कार्गो / कन्टेनर तथा पोत संबंधी प्रमारों के विषय में विभिन्न अन्य मार्गदर्शी बताये गए हैं इस स्थिति के मदद नजर और यह मानते हुए भी कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्रशुल्क की वैधता संशोधित व्यवस्था में, तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संशोधित मार्गदर्शियों का पालन किया गया है, केओपीटी को अपने कथित रूप से अन्तिम रूप दे दिए गए प्रशुल्क प्रस्ताव को फिर से देखना पड़ेगा। जैसाकि, केओपीटी के वर्तमान दरमान की व्यवस्था पहले ही समाप्त हो गई है, वर्तमान दरमान को जारी रखना आवश्यक हो गया है। अतएव, यह प्राधिकरण केओपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता को 30 सितम्बर 2005 तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान करने का इच्छुक है।

4. वेतन, दिहाड़ी, पेंशन संबंधी लाभ के बकाया और इन बकाया राशियों के भुगतान के लिए प्राप्त किए गए बैंक ऋण पर 31 मार्च 2001 तक जमा हुए देय ब्याज की मद में कुल देयता का संशोधित अनुमान 277.89 करोड़ रुपये है। इस विषय में पत्तन द्वारा प्रस्तुत की गई लेखा-परीक्षित स्थिति से पाया गया है कि पत्तन ने 31 जनवरी 2005 तक 249.04 करोड़ रुपये की देनदारियां निपटा दी हैं। इसने आगे बताया है कि 31 मार्च 2006 तक विशेष दर से 56.27 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। विशेष दर से उत्पन्न हुआ और होने वाले राजस्व को, बकाया देनदारियों और पहले ही निपटा दी गई बकाया देनदारियों की मात्रा की मद में उद्भूत कुल संशोधित देयताएँ लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित कर दी गई हैं।

5. जैसाकि पहले बताया जा चुका है, केओपीटी ने 10% की विशेष दर को 31 जुलाई 2006 तक विस्तार प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। चूंकि केओपीटी को संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी ध्यान में रखते हुए अपने दरमान के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव संशोधित करना है, संशोधित प्रशुल्क शासन के अन्तर्गत अपनाए जाने वाले राजस्व माडल के संदर्भ से विशेष दर की मात्रा और उसकी अवधि का आकलन किया जा सकता है। उस समय तक, केओपीटी द्वारा बताई गई बकाया देनदारियों की मात्रा पर विचार करते हुए, यह प्राधिकरण, लागू होने वाले प्रमारों पर 10% की विशेष दर, को 30 सितम्बर 2005 तक की अवधि के लिए विस्तार प्रदान करने का इच्छुक है।

6. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण केओपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता को 30 सितम्बर 2005 तक की अवधि के लिए विस्तार प्रदान करता है। 10% की विशेष दर, लागू प्रमारों पर 1 अप्रैल 2005 से 30 सितम्बर 2005 तक लगाई जाती रहेगी।

7. केओपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह प्रशुल्क निर्धारण हेतु संशोधित मार्गदर्शी ध्यान में रखते हुए, अपने दरमान की सामान्य समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव हर हाल में 30 जून 2005 तक अवश्य प्रस्तुत कर दे।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/05-असाधारण]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 28th April, 2005

No. TAMP/ 80/2000-CPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Kolkata Port Trust for extension of the validity of the existing Scale of Rates and the special rate fixed to meet the liability on account of arrears of salary, wages and pension as in the order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports****Case No. TAMP/80/2000 - CPT**

The Kolkata Port Trust

---

Applicant

**ORDER**(Passed on this 25<sup>th</sup> day of April 2005)

This case relates to a proposal from the Kolkata Port Trust (KOPT) for extension of the validity of the existing Scale of Rates and the special rate fixed to meet the liability on account of arrears of salary, wages and pension beyond 31 March 2005.

2.1 The Scale of Rates of the Kolkata Port Trust (KOPT) with respect to cargo and vessel related charges was last revised in April 2001 with a validity period of two years. To meet the liability on account of arrears of salary, wages and retirement benefits arising out of various Government Orders issued till 31 December 2000, the KOPT was permitted to levy a special rate as a percentage of various charges notified in the Scale of Rates for a period of 4 years commencing from the financial year 2001-02. The special rate for the financial years 2001-02 and 2002-03 was prescribed at 10% of the respective charges payable by the port users. The quantum of special rate for subsequent period was to be fixed after a review of the financial position at the end of the initial two years period.

2.2. Subsequently, on the proposals of the KOPT the special rate was allowed to continue to be levied at 10% of the applicable charges till end of the financial year 2004-05 and the validity of the Scale of Rates was extended accordingly. The KOPT was directed to submit its proposal for general review of the Scale of Rates as well as its proposal for review of estate rentals at Kolkata latest by end of September 2004.

3.1 The KOPT has informed that its has already finalised its proposal for general revision of Scale of Rates and stated that the tariff proposal would be placed before its Board of Trustees for consideration in its next meeting. It may be significant to note that in the meanwhile, the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (MSRTH) has recently issued revised guidelines for tariff fixation under Section 111 of the Major Port Trust Act, 1963. In compliance with the direction from the MSRTH, the Authority has notified the revised guidelines for tariff fixation on 31 March 2005.

3.2 The revised guidelines prescribe specific guidelines to be followed while filing the cost statement for tariff revision / fixation with reference to treatment of royalty/ revenue share receivable by the Port Trust, categorisation of assets, computation of return on capital employed, computation of depreciation etc., various other guidelines have been prescribed in respect of cargo / container and vessel related charges. In view of this

position, and also recognising that validity of the tariff to be approved by the Authority will be for a period of three years under revised arrangement, the KOPT may have to re-look at the tariff proposal reportedly finalised by it to ensure that it complies with the revised guidelines. Since the validity of the existing Scale of Rates of KOPT has already expired, continuation of the existing Scale of Rates is necessary. This Authority is, therefore, inclined to accord approval to extend the validity of the existing Scale of Rates of the KOPT upto 30 September 2005.

4. The revised estimates of the total liability on account of arrears of salaries, wages, pension benefits and interest payable on bank loans obtained for releasing arrears, accrued upto 31 March 2001 is reported at Rs.277.89 crores. From the audited position furnished by the port in this regard, it is found that the port has discharged this liability to the extent of Rs.249.04 crores upto 31 January 2005. It has further stated that Rs.56.27 crores is estimated to be realised out of the special rate upto 31 March 2006. The revenue generated and to be generated from the special rate, the total revised liabilities accrued on account of arrear liabilities and the quantum of arrear liabilities already discharged have been certified by the audit.

5. As stated earlier, the KOPT has proposed to extend the 10% special rate upto 31 July 2006. Since the KOPT has to revise its proposal for general revision of its Scale of Rates bearing in mind the revised tariff guidelines, the quantum and duration for special rate can be further assessed with reference to the revenue model to be adopted under the revised tariff regime. Till such time, considering the quantum of arrear liabilities reported by KOPT, this Authority is inclined to approve the extension of 10% special rate on the applicable charges for a period upto 30 September 2005.

6. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the extension of the validity of the existing Scale of Rates of KOPT for a further period upto 30 September 2005. The special rate will continue to be levied at 10% of the applicable charges for the period 1 April 2005 to 30 September 2005.

7. The KOPT is directed to submit its proposal for general review of its Scale of Rates bearing in mind the revised guidelines for tariff fixation on or before 30 June 2005 positively.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT/III/IV/143/05-Exty.]